दिया है। इसलिए इस बारे में यदि आज कुछ कदम उठाना हो और सुधार करना हो, तो जिस फोर्म ने यह सलाह दी है, उनके पास हमें जाना पड़ेगा। उनकी मीटिंग बुलाने के लिए और उनकी सलाह लेने के लिए मेरी तैयारी रहेगी।

Relief package for suicide prone areas

*83. SHRI VARINDER SINGH BAJWA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether any relief package has been announced for the suicide prone areas in the country for the benefit of farmers; and

(b) if so, the districts likely to be covered under that package?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI SHARAD PAWAR): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) A special package for mitigating the stress of farmers for the six districts of Vidarbha region of Maharashtra, namely, Wardha, Yevatmal, Amravati, Akola, Buldana, and Washim, was announced by the Prime Minister during his visit of the region from 30th June to 1st July, 2006. The package aims at establishing a sustainable and viable farming and livelihood support system through debt relief to farmers, improved supply of institutional credit, non crop centric and integrated approach to agriculture, assured irrigation facilities, watershed management, better extension and farming support services, improved marketing facilities and subsidiary income opportunities through horticulture, livestock, dairying, fisheries, etc.

The Government is working out the rehabilitation package for the identified districts in the States of Andhra Pradesh, Karnataka and Kerala on the lines of the package that has been announced for the Vidarbha region of Maharashtra. The districts to be covered in these three States are:

Karnataka - 6 Districts

- Belgaum, Hasan, Chitradurga, Chikmagalur, Kodagu and Shimoga.

Kerala - 3 Districts

- Wayanad, Palakkad and Kasargod.

Andhra Pradesh - 16 Districts

- Prakasam, Guntur, Nellore, Cuddappa, Chittor, Ananthapur, Kurnool, Adilabad, Karimnagar, Khammam, Mahabubnagar, Medak, Nalgonda, Nizamabad, Rangareddy and Warangal.

श्री वरिन्दर सिंह बाजवा: चेयरमैन साहब, माननीय कृषि मंत्री जी ने मेरे सवाल के लिखित जवाब में बताया है और सुसाइड प्रोन एरिया में इन्होंने महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में 6 डिस्ट्रिक्ट्स लिए हैं, जहां पर पैकेज दिया है। उसके बाद उन्होंने बताया है कि गवर्नमेंट आइडेंटिफाई कर रही है, कर्नाटक में 6 डिस्ट्रिक्ट, केरल में 3 डिस्ट्रिक्ट और आन्ध्र प्रदेश में 16 डिस्ट्रिक्ट हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पंजाब सैंट्रल पूल में सबसे ज्यादा फूड ग्रेन कंट्रीब्यूट करता है। पंजाब का किसान कर्जे में डूबा हुआ है और वहां सुइसाइड हो रहे हैं और पंजाब सरकार को कोई फिक्र नहीं है। वहां पर 1988 से लेकर आज तक 2116 आत्महत्याएं हुई हैं। गत तीन सालों में पंजाब के अकेले संगरूर डिस्ट्रिक्ट में 200 से अधिक आत्महत्याएं हुई हैं। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अभी तक पंजाब का कोई डिस्ट्रिक्ट क्यों आइडेंटिफाई नहीं किया गया है?

श्री शरद पवार: इसमें जिन चार स्टेटों का जिक्र किया गया है, इनमें सबसे ज्यादा आत्महत्याएं जिन राज्यों में और जिलों में हुई हैं, इनमें 16 डिस्ट्रिक्ट आन्ध्र प्रदेश के, तीन डिस्ट्रिक्ट केरल के, 6 डिस्ट्रिकट महाराष्ट्र के और 6 डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक के हैं। जहां तक पंजाब की बात है, पंजाब सरकार की तरफ से हमें जो रिपोर्ट मिली है, उसके मुताबिक पिछले दो-तीन सालों में वहां आत्महत्या करने वालों की कोई संख्या नहीं है। यह रिपोर्ट पंजाब सरकार ने लिखित रूप में भेजी है और इसके बेस पर यहां डिसिजन लिया गया है।

श्री वरिन्दर सिंह बाजवा: सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इसका क्या क्राइटेरिया है? ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आत्महत्या का मामला है। ...(व्यवधान)...

श्री वरिन्दर सिंह बाजवा: आप कहते हैं कि यह पंजाब गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, जो मैं बता रहा हूं। क्या जो पंजाब का किसान आत्महत्या करता है, उसको कोई इन्साफ नहीं मिलना चाहिए, उसको कोई कम्पेनसेशन नहीं मिलना चाहिए? उसके लिए आपने क्या किया है?

श्री शरद पवार: देश के किसी भी रिजन के किसान के सामने यदि आत्महत्या करने की नौबत आती है तो यह देश के लिए कोई अच्छी बात नहीं है और न ही हमें इस बारे में कोई

खुशी होती है। इस बारे में कई राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में, ऐसी स्थिति में किसानों को मदद करने की पालिसी तय की है और वे इस पर अमल कर रहे हैं। इन चार राज्यों में स्थिति ज्यादा गंभीर थी। खास तौर पर जो परिस्थिति पैदा हुई है, चाहे वायनाड डिस्ट्रिक्ट हो, पलाक्कड हो या कासरगोड हो, वहां पर पिछले कुछ सालों से स्थिति बहुत गंभीर हो रही थी। यह बात सरकार के सामने आई है। वैसी ही स्थिति आंन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के विदर्भ के 6 जिलों की थी। इसलिए इसके लिए एक अलग पैकेज तैयार करने का सुझाव था और इस तरफ से वह पैकेज तैयार किया गया है। अभी इस पर पहला पैकेज विदर्भ का तैयार हुआ है और बाकी तीन राज्यों के लिए हम पैकेज तैयार कर रहे हैं। इस बारे में हमने जो कदम उठाए हैं, इन चार स्टेट्स की स्थिति देखने के बाद, इसका अनुभव देखने के बाद, बाकी जिन जिलों में ऐसी परिस्थिति पैदा होगी, उन जिलों के बारे में भी कुछ करने की सरकार की तैयारी रहेगी।

श्री उदय प्रताप सिंह: सभापति महोदय, यह एक सर्वविदित सच्चाई है कि जो किसान आत्महत्या करते हैं, इसके पीछे 80 प्रतिशत मामलों में यह कारण होता है कि जो वे कर्जा लेते हैं, उसकी पूरी अदायगी नहीं कर पाते हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जब सबको यह सच्चाई विदित है, जो क्या आप सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजना बना रहे हैं, जो छोटे किसान हैं और जिनपर कम कर्जा है, उनके कर्जे को माफ करेंगे और बाकी को आसान किश्तों पर अदायगी करवाएंगे या ब्याज दरों में रियायत देंगे, क्योंकि जब तक यह काम नहीं होगा तब यह आत्महत्याओं का सिलसिला बंद नहीं होगा?

श्री शरद पवार: सभापति जी, इन आत्महत्याओं के जो कारण हैं, इनकी depth में जाने के बाद यह बात साबित हुई है कि किसानों के ऊपर कर्ज का बहुत बोझ है और उसे उतारने की उनमें ताकत नहीं है तथा उनको नया कर्ज मिलने का रास्ता बंद हो गया है। यह किसानों के द्वारा आत्महत्याएं किए जाने का प्रमुख कारण है। इसके लिए पिछले 2 सालों में कुछ कदम उठाए गए हैं। उनमें एक कदम यह है कि हमारे total agricultural credit में कैसे वृद्धि हो सकती है, इस पर ध्यान दिया गया। दो साल पहले किसानों को crop loan के लिए जो 86,000 करोड़ रुपए मिलते थे, इस साल इसे बढ़ाकर हम एक लाख, 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचे हैं, फिर भी हम खुश नहीं हैं क्योंकि अभी भी sizeable section is still not getting the credit.

सभापति जी, दूसरी बात यह है कि इसका interest rate एक बहुत बड़ी समस्या थी, इसलिए पिछले बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने देश के सामने यह बात साफ कही है कि आगे से 3 लाख रुपए तक 7 परसेंस rate of interest पर कर्ज मिलेगा और इस दिशा में शुरुआत हुई है। जहां तक 4 राज्यों की स्थिति का सवाल है और जिन जिलों के लिए यह पैकेज तैयार किया

गया, इन जिलों में किसानों के ऊपर जो बोझ है, इसकी re-scheduling की गई है, पहले 2 साल के लिए moratorium दिया गया है और इसका total interest माफ करने का decision लिया गया है।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, एक बात बताइए कि किसान कर्ज लेता है, कर्ज लेने के कारण क्या हैं और उन कारणों की आप किस प्रकार से रोकथाम कर रहे हैं, जिससे उसको कर्ज न लेना पड़े और वह न मरे।

श्री शरद पवार: इसमें दो किस्म के कारण होते हैं। एक तो वे capital investment के लिए पैसे लेते हैं। यदि किसान को कुआं खोदना हो, lift irrigation scheme लगानी हो, ट्रैक्टर खरीदना हो, औजार खरीदने हों, तो इसके लिए वे कर्ज लेते हैं।

श्री सभापति: इसके कारण आत्महत्या नहीं होती है।

श्री शरद पवार: दूसरा, वे crop loan के लिए भी कर्ज लेते हैं। तीसरी बात यह है कि जब तक उनको अपनी उपज की ठीक कीमत नहीं मिलेगी, तब तक यह काम नहीं हो सकता है। जब ठीक तरह से उनकी उपज की कीमत मिलने का प्रबंध हो जाएगा, तो शायद यह कर्ज लेने का रास्ता बंद हो सकता है। इसलिए हमें ठीक तरह से उनकी उपज की कीमत देने का प्रबंध करना होगा, लेकिन यदि हम ऐसे कदम उठाएंगे कि किसानों को इस कीमत पर यहीं माल देना चाहिए, तो उनकी परिस्थिति में बदलाव नहीं आएगा। इसलिए जो liberalisation proces वहां शुरू हुआ है, इसका ultimate फायदा किसानों को होगा। इससे ज्यादा कदम उठाने की आवश्यकता है, आपकी इस भावना से मैं सहमत हूं।

श्री सभापति: कुरियन जी, आप पूछिए।

श्री उदय प्रताप सिंह: सभापति जी, इसमें एक बात रह गई ...(व्यवधान) प्राकृतिक आपदा के कारण जब किसान प्रभावित होता है, उसके लिए क्या आप कुछ सहूलियत देंगे?

श्री सभापति: कुरियन जी, आप पूछिए।

PROF. P.J. KURIEN: Sir, the hon. Minister has mentioned about a package. Unfortunately, in Kerala, there are two districts Idukki and Alleppey where the farmers have also committed suicides. The farmers are very badly affected because they are not able to repay loans. ...*(Interruptions)*...

श्री दत्ता मेघे: सभापति जी, मैं यह ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अगर आप पहला क्वेश्चन नहीं करते, तो मैं allow कर देता।

PROF. P.J. KURIEN: Will the hon. Minister consider including these districts also in the package?

SHRI SHARAD PAWAR: The proposal which we got from the Government of Kerala is for Wayanad, Palakkad and Kasargod. It is true that many hon. Members of Parliament from Kerala met me and they have given some additional names of districts like Idukki. There are a number of other proposals also. But, we would like to implement this project first. After that, we will consider about the additional districts.

श्री विजय जे. दर्डा: सभापति जी, हमारे यहां ...(व्यवधान)

श्री सभापति: वह ठीक है, आप इसमें प्राथमिकता ले रहे हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है ...(व्यवधान) आत्महत्या के मामलों में महाराष्ट्र सबसे आगे बढ़ गया, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए ...(व्यवधान) पहले राजकुमार धूत जी को पूछने दीजिए...(व्यवधान)

श्री राजकुमार धूत: सभापति जी, मैं आपके जरिए महाराष्ट्र के किसानों की एक गंभीर समस्या के बारे में मंत्री जी से कुछ कहना चाहता हूं कि आज महाराष्ट्र में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: सवाल पूछ लीजिए ...(व्यवधान) अगर आप बोलेंगे, तो ये सुनेंगे ही नहीं।

श्री राजकुमार धूत: सभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में बहुत शूगरकेन आने वाला है, उसका अच्छा उत्पादन होने वाला है, लेकिन महाराष्ट्र की शूगर मिलों की हालत ऐसी नहीं है कि वे इनको खरीद सकेंगी। इसलिए मैं मंत्री जी से विनती करूंगा कि वे कुछ ऐसा करें कि पूरा शूगरकेन, शूगर मिलों में जाए, शूगर मिलों से शूगर निकले और लोगों को सस्ती शूगर मिले। यह महाराष्ट्र की बहुत गंभीर समस्या है।

श्री सभापति: यह बहुत गंभीर समस्या है और मंत्री जी इसे गंभीरता से लें।

SHRI K. CHANDRAN PILLAI: Sir, Prof. Kurien has put up the issue of including in the list two more districts from Kerala—Idukki and Alleppey. Already three districts are included in the list. I would like to know on that.

SHRI SHARAD PAWAR: I have already replied, Sir, that whatever proposals we got from the States, we would like to implement those in these districts. After the execution of these proposals only would we think about some other districts.

श्री विजय जे॰ दर्डा: धन्यवाद सर। हाल ही में विदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी कृषि मंत्री जी ने वहां visit किया और उन्होंने किसानों की समस्या को समझ कर नागपुर में एक पैकेज घोषित किया था। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उस पैकेज के घोषित करने के बावजूद भी आज भी लगातार आत्महत्याएं हो रही हैं, इसमें प्रतिदिन 3 का average आ रहा है, तो क्या आपने इस दृष्टि से भी विचार किया है कि उसके अन्दर कोई ब्यूरोक्रेटिक एंगल तो नहीं है कि जिसकी वजह से उनकी प्रताड़ना रही है जिसकी वजह से वे लोग आत्महत्या कर रहे हैं? साथ-ही-साथ में आपको यह बताना चाहूंगा कि आपने अभी जो पैकेज घोषित की है, उसमें कुओं के ऊपर विचार नहीं किया गया है, आप कलेक्टर को आदेश देकर कुएं खोदने के लिए आदेश मिल जाते, तो वहां पर इस वक्त कुंआ खोद कर बारिश का लाभ ले सकेंगे अभी पानी मिल सकता है और किसानों की सिंचाई की समस्या भी दूर हो सकती है, आज वहां पर करीब 18 हजार कुओं की आवश्यकता है। कृपया मंत्री जी बताएं।

श्री सभापति: मेघे जी, आप भी अपना प्रश्न पूछ लीजिए, ये दोनों का जवाब एक साथ दे देंगे, क्योंकि टाइम इतना ही बचा है।

श्री शरद पवार: अभी जिस पैकेज की बात बताई गई है, इसमें सबसे ज्यादा आत्महत्या श्री दर्डा जी जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में हुई है और यह बड़े दुख की बात है। इनके डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा suicide हुई है। ...(**व्यवधान**)...

श्री विजय जे. दर्डा: सर, मेरे यहां सबसे ज्यादा suicide हुई है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य थोड़ा शान्त रहें, क्योंकि यह क्वैश्चन बड़ा important है।

श्री शरद पवार: वहां जो स्थिति है, उसमें सुधार करने के लिए कुछ कदम उठाने की आवश्यकता थी। लोकल लीडरशिप, लोकल गवर्नमेंट, सभी के साथ बातचीत करके यह पैकेज तैयार किया गया हैं। इसमें इन सभी एरियाज़ की सबसे पहली डिमांड यह थी कि हमारे यहां irrigation की facility जल्द-से-जल्द पूरी होनी चाहिए। इसमें एक decision यह लिया गया कि यवतमाल डिस्ट्रिक्ट और बाकी 5 डिस्ट्रिक्ट्स में जितने minor, medium और major irrigation के projects के proposals हैं, उन सभी के लिए एआईडीसी, गवर्नमेंट ऑफ् इंडिया के माध्यम से राशि का प्रावधान किया जाएगा और 3 सालों में ये सभी projects पूरे कर लिए जाएंगे। इसमें यह सबसे बड़ा important कदम उठाया गया है।

श्री सभापति: श्री दत्ता मेघे ...(**व्यवधान**)... आप बैठिए ...(**व्यवधान**)... कोई सवाल नहीं होगा ...(**व्यवधान**)... कोई रेकार्ड पर नहीं जाएगा ...(**व्यवधान**)... एक मिनट है, let him put his question. आप बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री दत्ता मेघे: सर, आज की हालत यह है कि हम हमारे नेता शरद पवार जी का जरूर स्वागत करते हैं कि वहां 3,700 करोड़ रुपए आए हैं, लेकिन वहां पर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सेक्रेटरीज़ हैं, वे हमें 5 करोड़ के ऊपर नहीं दे रहे हैं।

श्री सभापति: बस कीजिए। एक मिनट बचा है, वे फिर जवाब नहीं देंगे।

श्री दत्ता मेघे: ऐसा होने के बाद यह पैसा उन्हें न मिलने की वजह से और भी 60 लोगों ने आत्महत्या की है और उसके बाद और भी लोग आज भी आत्महत्या कर रहे हैं। इन ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, जो इसमें आ रहे हैं, आप क्या कार्रवाई करेंगे? ...(**व्यवधान**)...

श्री वी. हनुमंत राव: सर, तेलंगाना के लिए भी एक पैकेज दिया जाना चाहिए, क्योंकि तेलंगाना में ज्यादा लोग मरे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: इनका भी ध्यान रखिए ...(**व्यवधान**)... ठीक है, हो गया ...(**व्यवधान**)...

श्री शरद पवार : मेघे जी ने जो बात बताई, यह बात यच है कि पिछले महीने भी वहां आत्महत्या का नम्बर ज्यादा रहा है, ऐसी बात हमारे सामने आई है। सर, मगर एक बात यह है कि irrigation के projects के लिए कुछ पैसा दिया गया, जैसे दो हजार या 2.5 हजार करोड़ रुपए, मगर irrigation के ये projects एक महीने में पूरे नहीं हो जाएंगे। इन्हें पूरा करने के लिए 3 साल का समय दिया गया है। इसमें यह पैकेज ...(**व्यवधान**)...

श्री वी. हनुमंत राव: सर, आन्ध्र प्रदेश के लिए भी बोलिए।

श्री शरद पवार: आन्ध्र प्रदेश के लिए हमारे सामने 16 डिस्ट्रिक्ट्स के proposals आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने दिए हैं और हम इस पर अमल कर रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Increasing cases of breast cancer

*84. SHRI SANJAY RAUT: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that breast cancer cases are alarmingly increasing in the country since last three years;